किन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और सरकार द्वारा ऐसे प्रशिक्षण पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :

(क) स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के पास 6 वायुयान हैं इनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	स्टेशन-स्थान	वायुयान की किस्म	मूल लागत
1.	लोहा और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, "सेल", रांची	(1) क्वीन एयर-65	11,72,171.38
		(2) ट्विन बोनान्जा डी 50 ई	4,39,478.59
2.	इस्को, बर्नपुर	(1) क्वीन एयर	9,18,262.04
		(2) ट्विन बोनान्जा	6,46,781.84
3.	भिलाई	किंग एयर एफ-90	2,80,10,366.0
4.	बोकारो	सुपरकिंग एयर-बी-200	3.9 करोड़ (लगभग)

(ख) "सेल" ने सूचित किया है कि इन वायुयानों पर गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। श्री एस.बी. सिंह, जिसके पास प्राइवेट पायलट लाइसेंस था, ने बोकारो स्टील संयंत्र का वायुयान, वायुयान उड़ाने की अनुमति के लिए आवेदन करने के बाद कुछ घंटे (9 घंटे 55 मिनट) निगरानी में उड़ाया था। बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा 'सेल' निगमित कार्यालय को किया गया अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। अतः बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा प्रणोदन की लागत के रूप में श्री एस.बी. सिंह से 21,600/- रु. वसूल किए गए थे।

Cases of Corruption and Irregularities in Steel Companies/Undertakings

2136. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of STEEL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several cases of corruption and charges of irregularities have been found against some senior officers of different companies/Undertakings till 30th April, 1993 under his Ministry;

(b) whether it is a fact that the number of cases have been on increase compared to previous three years;

(c) whether Government have found out ways to deal with cases of corruption expeditiously; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) to (d) The Vigilance Unit in the Ministry of Steel deals with the vigilance cases of only the Board-level officers of Public Sector Undertakings (PSUs). There has been no case in which the Ministry was required to proceed against any Board level officer of Public Sector Undertakings (PSUs) on charges of corruption/irregularities during the last three years and upto 30th April, 1993. Action on cases against below Board-level officials, where necessary, is taken by the PSUs themselves, as per the existing procedure.

इस्पात की उत्पादन लागत

2137. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में इस्पात की उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हम पिछले चार दशकों के दौरान इस्पात के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात के मूल्य की तुलना में हमारा इस्पात महंगा होता है;